प्रेषक.

एस० रामास्वामी, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 🛴 जून, 2011

विषय:

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पी.एम.आर.वाई. प्लस योजना में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः860उ०नि०(दो)—13 / बजट—मॉग / 2011—12 दिनांक 25 मई, 2011 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः209 / XXVII(1) / 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011—12 हेतु पीएमआरवाई प्लस योजनान्तर्गत ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2— उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितात आवश्यक है तथा इस संबंध में समय—समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघन होता हो।
- 3— स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा। अगली किश्त की धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब पिछली किश्त का व्यय विवरण प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। त्रैमासिक व्यय की फेजिंग भी शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 4— स्वींकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2012 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 5— उक्त योजना पर धनराशि का व्यय करते समय योजना से सम्बन्धित समस्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा और अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग करके इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

6— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के अनुदान संख्या—23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851—ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00—आयोजनागत, 102—लघु उद्योग, 22—पीएमआरवाई प्लस योजना,—00—, 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः209 / XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय, (एस० रामास्वामी) प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1420/VII-II-11/85-उद्योग/05 तद्दिनांकित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
- 3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
- 4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
- 6. अपर सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 8. वित्त अनुभाग-2
 - 9. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह सक्त) अनु सचिव।